

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7
संख्या: 203/xxvii(7)/2009
देहरादून, दिनांक: 21 जुलाई, 2009

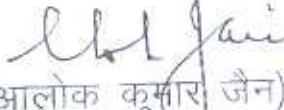
कार्यालय ज्ञाप

विषय:- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रैक्वोरमेंट) नियमावली, 2008 के अधीन राज्य के सहकारी संस्थाओं से अधिप्राप्ति की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रैक्वोरमेंट) नियमावली, 2008 के अध्याय-2 में 'सामग्री' की अधिप्राप्ति हेतु रू0 15,000 तक की सामग्री का क्रय बिना कोटेशन के, रू0 15,000 से ऊपर तथा रू0 1 लाख तक की सामग्री का क्रय परचेज कमेटी के द्वारा, रू0 15 लाख तक की सामग्री का क्रय "लिमिटेड टेण्डर इन्क्वायरी" के द्वारा तथा रू0 25 लाख तथा उससे अधिक की सामग्री का क्रय "एडवर्टाईज्ड टेण्डर इन्क्वायरी" के द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। उक्त के अतिरिक्त राज्य में निर्मित लघु/काटेज/खादी उद्योगों के उत्पादों को 10 प्रतिशत की सीमा तक मूल्य तथा क्रय वरीयता शासन की नीतियों के अनुसार क्रय किये जाने की व्यवस्था है।

2- भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग - के कार्यालय ज्ञाप सं0 14/12/94-वेलफेयर(vol.II) दिनांक 5-7-2007 के द्वारा केन्द्रीय भण्डार, एन0सी0सी0एफ0 तथा अन्य मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज से सामग्री क्रय की व्यवस्था निरूपित की गई हैं। अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ के पत्र संख्या 10147 दिनांक 4-12-2008 के संदर्भ में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सहकारी संघों के माध्यम से रू0 15000 से अधिक तथा रू0 1,00,000(रू0 एक लाख मात्र) तक की लागत की सामग्री का क्रय संबंधित विभाग द्वारा राज्य सहकारी संघ से मूल्य की औचित्यता से सन्तुष्ट होते हुए सीधे क्रय समिति के माध्यम से करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्रय समिति द्वारा सामग्री की गुणवत्ता, विशिष्टता तथा दरों की युक्तयुक्तता(Reasonableness) प्रमाणित की जाएगी। रू0 1,00,000(रू0 एक लाख मात्र) की अधिकतम सीमा को बढ़ाये जाने के लिए सप्लाय ऑर्डर को किसी भी परिस्थिति में टुकड़ों में नहीं तोड़ा जाएगा। उक्त के अतिरिक्त रू0 15,00,000(एक पन्द्रह लाख मात्र) सीमा तक की सामग्री के क्रय हेतु अपनाई जाने वाली लिमिटेड टेण्डर इन्क्वायरी की प्रक्रिया में राज्य सहकारी संघ को भी रजिस्टर्ड सप्लायर के रूप में निविदा दाता की सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

4. उक्त व्यवस्था दिनांक: 31-3-2010 तक के लिए ही लागू होगी।


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या: 203/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
6. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
7. स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
8. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ ।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से
(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।